संचिका सं0-पी0एम0यू0/बी0सी0डी0-30/2016........9910(भ)/अनु॰

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 06/10/2016

विषयः- भवन निर्माण विभाग के माध्यम से खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा आवंटित कार्यो की अद्यतन समीक्षात्मक टिप्पणी के संबंध में।

प्रसंगः- विभागीय पत्रांक 8264(भ)अनु0 दिनांक 26.08.2016

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के क्रम में कहना है कि खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के माध्यम से कियान्वयन हेतु 438 योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। इन कार्यो की माह अगस्त, 2016 तक की प्रगति की स्थिति निम्नवत है:-

(1) **<u>भौतिक प्रगतिः-</u>**

- कुल 438 योजनाओं में से 384 योजनाओं का कार्य पूर्ण हो गया है, 3 योजनाओं का कार्य प्रगति में है, 20 योजनाएं निविदा/प्राक्कलन/मिट्टी जांच में है, 2 योजनाएं पुनरीक्षण में है एवं 29 योजनाओं के लिए स्थल समस्या है, जिसकी सार विवरणी परिशिष्ट 'क' पर द्रष्टव्य है।

(2) **वित्तीय प्रगतिः-**

- वित्तीय वर्ष 2016-17 में माँग संख्या-3 के अन्तर्गत 7466.00 लाख का वजट उपबंध है।

(3) **प्रशासी विभाग के ध्यानाकर्षण हेतु मुख्य मुद्देः-**

- पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति हेतु लंबित योजनाओं पर शीघ्र पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाए।
- जिन योजनाओं का स्थल अनुपलब्ध है, उन्हें स्थगित किया जाय।
- वर्ष 2016-17 में बजट उपबंध 7466 लाख के विरूद्ध कोई स्वीकृति नही प्राप्त है तथा भवन निर्माण विभाग द्वारा निर्माणाधीन गोदामों के संगत शीर्ष में राशि का उपबंध नही है, जबकि वर्तमान वित्तिय वर्ष में निर्माणाधीन गोदामों के लिये लगभग 2.50 करोड़ की आवश्यकता है।

(4) <u>**अनुश्रवण एवं मूल्यांकन की व्यवस्था**</u>

- भवन निर्माण विभाग के स्तर पर आपके विभाग की योजनाओं के अनुश्रवण के लिए श्री रविन्द्र प्रसाद सिंह, उपनिदेशक-2 को दायित्व दिया गया है जिनका ई-मेल dd2.bcd@gmail.com तथा मोबाईल नं0 9430965732 है।
- भवन निर्माण विभाग द्वारा Project Management Information System विकसित किया गया है, जो विभाग के वेबसाईट पर उपलब्ध है। इस अनुश्रवण व्यवस्था में सभी योजनाओं की अद्यतन भौतिक एवं वित्तीय स्थिति Upload करायी जा रही है। आपसे अनुरोध है कि प्रशासी विभाग के स्तर से भी योजनाओं की प्रतिवेदित भौतिक/वित्तीय प्रगति की समीक्षा की जाए। इस कम में किसी बिन्दु पर इस विभाग के स्तर से कार्रवाई अपेक्षित हो तो कृपया अवगत कराया जाए।
- उल्लेखनीय है कि क्षेत्रीय पदाधिकारियों की मासिक समीक्षा बैठक में भी इस समीक्षा टिप्पणी में अंकित बिन्दुओं पर समीक्षा की जाएगी। उस बैठक में अद्यतन विवरणी के साथ स्वयं या नोडल पदाधिकारी को भाग लेने हेतु प्रतिनियुक्ति करने की कृपा की जाए।

अनु0:-यथोक्त

विश्वासभाजन

(अमृत लाल मीणा)

सरकार के प्रधान सचिव।